Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 5.146
Volume - 5, Issue - 9, September - 2022 Publication Date: 30/09/2022

DOIs:10.2018/SS/202209011 --:-- Research Article

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) : एक अध्ययन

हरीश जनागल
व्यावसायिक प्रशासन विभाग, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन संकाय
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर (राज)
Email: harishjanagal@gmail.com

सारांश : भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं। अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लघु उद्योगों के विकास के साथ देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास भी संभव हैं। इन उद्योगों द्वारा देश में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई हैं। तथा सकल घरेलु उत्पाद में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान हैं। प्राचिन समय से ही भारत में लघु उद्योगों द्वारा अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हैं। इन वस्तुओं का भारत में ही नही, अपितु विदेशों में भी निर्यात किया जाता हैं। उद्योगों को पूंजी पर आधारित अनेक वर्गो में विभाजित किया गया हैं। जैसे:- लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रह उद्योग, वृहद उद्योग आदि। वर्तमान में वृहद उद्योगो की ही तरह लघु उद्योगो ने अपना वर्चस्व बनाए रखा हैं। लघु उद्योग वे इकाइयां हैं जो मध्यम स्तर के निवेश की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम बल की मात्रा भी कम होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का अपेक्षाकृत उत्पादन होता है। वे पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन और प्रबंधन, आदानों और आउटपुट के प्रवाह आदि के मामले में बड़े पैमाने के उद्योगों से अलग हैं।

शब्द कुंजी : एमएसएमई, लघु उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार और भारतीय अर्थव्यवस्था, निवेश, विनिर्माण।

1. प्रस्तावना :

भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं। अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लघु उद्योगों के विकास के साथ देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास भी संभव हैं। इन उद्योगों द्वारा देश में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई हैं। तथा सकल घरेलु उत्पाद में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान हैं। प्राचिन समय से ही भारत में लघु उद्योगों द्वारा अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हैं। इन वस्तुओं का भारत में ही नही, अपितु विदेशों में भी निर्यात किया जाता हैं। उद्योगों को पूंजी पर आधारित अनेक वर्गो में विभाजित किया गया हैं। जैसे:- लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रह उद्योग, वृहद उद्योग आदि। वर्तमान में वृहद उद्योगो की ही तरह लघु उद्योगो ने अपना वर्चस्व बनाए रखा हैं। लघु उद्योग वे इकाइयां हैं जो मध्यम स्तर के निवेश की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम बल की मात्रा भी कम होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का अपेक्षाकृत उत्पादन होता है। वे पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन और प्रबंधन, आदानों और आउटपुट के प्रवाह आदि के मामले में बड़े पैमाने के उद्योगों से अलग हैं। वे निम्नलिखित आधारों पर भी कुटीर उद्योगों से भिन्न हैं - उत्पादन में मशीनीकरण की डिग्री, मजदूरी मजदूरों का अनुपात और परिवार के मजदूर, बाजार का भौगोलिक आकार, नियोजित पूंजी आदि। लघु उद्योगों को तीन प्रकार के उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है.

1. सूक्ष्म उद्योग 2. लघु उद्योग 3. मध्यम उद्योग

निवेशित राशि के आधार पर वर्गीकरण:- भारत सरकार ने वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया था जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में 'प्लान्ट एवं मशीनरी' में निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी।

निर्माणाधीन प्रकृति के अनुसार :- इसके अनुसार -

(i) सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग है जहां संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपये से अधिक निवेश नहीं है।

(ii) लघु उद्योग वह उद्योग है जहां संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपये से अधिक निवेश है लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम निवेश है।

(iii) मध्यम उद्योग वह उद्योग है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में पाँच करोड़ रुपये से अधिक निवेश है लेकिन दस करोड़ रुपये से कम निवेश हो।

सेवा उद्योग की प्रकृति के अनुसार :- इसके अनुसार

(i) सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग है जहां उपकरण में 10 लाख रुपये से अधिक निवेश नहीं है।

(ii) लघु उद्योग वह उद्योग है जहां उपकरण में 10 लाख रुपये से अधिक निवेश है लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं है।

(iii) मध्यम उद्योग वह उद्योग है जहां उपकरण में 2 करोड़ रुपये से अधिक अधिक निवेश है लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम निवेश है ।

टर्नओवर राशि के आधार पर वर्गीकरण:- भारत सरकार ने वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया था जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में 'प्लान्ट एवं मशीनरी' में निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी। किन्तु 7 अप्रैल,2018 से एक नई परिभाषा लागू है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इस संशोधन के बाद अब "प्लांट और मशीनरी" में निवेश की जगह "टर्नओवर" के आधार पर MSMEs वर्गीकरण किया जायेगा। किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन, प्रसंस्करण अथवा परिरक्षण करने वाले उद्यम इस श्रेणी में शामिल किये जाते हैं। मुख्य रूप से लघु उद्योगों को उनमें टर्नओवर राशि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

विनिर्माण क्षेत्र -

(i) सूक्ष्म उद्योग - सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग है जिसका वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम हो।
(ii) लघु उद्योग - लघु उद्योग वह उद्योग है जिसका वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से अधिक व 75 करोड़ से कम हो।
(iii) मध्यम उद्योग -- मध्यम उद्योग वह उद्योग है जिसका वार्षिक टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से अधिक व 250 करोड़ से कम हो।

सेवा क्षेत्र -

(i) सूक्ष्म उद्योग - सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग है जिसका वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम हो।
(ii) लघु उद्योग - लघु उद्योग वह उद्योग है जिसका वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से अधिक व 75 करोड़ से कम हो।
(iii) मध्यम उद्योग - मध्यम उद्योग वह उद्योग है जिसका वार्षिक टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से अधिक व 250 करोड़ से कम हो।

2. लघु उद्योग के उद्देश्य :

1. लघु उद्योग का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है।
2. आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना है।
3. लघु उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विक्रेन्द्रीयकरण सम्भव है। ससे देश का आर्थिक विकास प्रौद्योगिक सन्तुलन एवं क्षेत्रीय प्रौद्योगिक विषमता को कम करते हुए सम्भव होता है।
4. लघु उद्योगों के माध्यम से देश की सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित रहती है। अधिकाशतः लधु उद्योगों द्वारा कलात्मक एवं परम्परागत वस्तुओं का निमार्ण किया जाता है एवं अधिकांशतः ये उद्योग श्रम प्रधानता आधारित होते है इस कारण उद्योगों में पारस्परिक सद्भावना, सहकारिता, समानता व भाईचारेकी भावना मजबूत होती है।
5. लघु उद्योग प्राकृतिक संसाधानों का अनुकूलतम उपयोग कर सके ।
6. मानवीय मूल्यों की दृष्टि से 'सादा जीवन उच्च विचार' की भावना का सृजन कर सके ।
7. व्यापार एवं भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने हेतु अत्याधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करें।
8. आमजन को श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना।

3. भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की भुमिका :

भारत एक विकासशील देश हैं। यहां की अधिकांशत: जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हैं। कृषि के पश्चात् लघु उद्योग ही हैं, जिस पर भारत की अधिकांश जनसंख्या आश्रित हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होने के कारण उनका समुचित उपयोग देश के आर्थिक विकास में चार चाँद लगा सकता हैं। प्राकृतिक संसाधनों का देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनके समुचित दोहन से देश का तीव्र गति से विकास होगा। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के स्वरुप को समझने में औद्योगिक ढांचे का महत्वपूर्ण स्थान हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरुप को समझने हेतु भी इसकी आवश्यकता होती हैं। लघु और कुटीर उद्योगों ने भारतीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र की संरचना और प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भाषा की दृष्टि से यह सामान्य प्रवृत्ति रही है कि कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और लघु उद्योग का अर्थ एक साथ प्रयोग किया जाता है, जबकि इन दोनों में मूलभूत अन्तर है। कुटीर उद्योग एक परिवार (कुटुंब) के सदस्यों द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से चलाए जाते हैं। इनमें पूंजी निवेश नाममात्र का ही होता है। उत्पादन भी अक्सर हाथ से किया जाता है। कुटीर उद्योग में परंपरागत तरीके से चल रही उत्पादन प्रक्रिया में कोई वैतनिक मजदूर नहीं होता हैं।

लघु व्यवसाय या छोटे क्षेत्र जैसा नाम से इंगित होता है लघु उद्योग होते हैं। लघु उद्योग देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण खंड है। यह क्षेत्र बड़ी संख्या में उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुंए एवं सामान के उत्पादन में योगदायी है। लघु व्यवसाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपंजीबद्ध है और असंगठित क्षेत्र में स्थित है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सामान्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और भारत विशेष रूप से समान, समावेशी और रोजगार के अनुकूल आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में है। यह क्षेत्र कम पूंजी की आवश्यकता,

उच्च रोजगार सृजन, औद्योगिक गतिविधि के विकेंद्रीकरण, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और उद्यमशीलता के आधार के विस्तार जैसे निहित लाभों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इन उद्यमों की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-

(अ) कुटीर उद्योग:- यह वह उद्योग है जो सामान्यतः कृषि और ग्रामीण एवं शहरी सदृश क्षेत्रों में अंश कालीन/ पूर्णकालीन पेशों से जुड़े हैं।

(ब) कृषि आधारित उद्योग - यह उद्योग कृषि उत्पादन पर आधारित हैं। कृषि आधारित उद्योग कुटीर स्तर, लघु स्तर या दीर्घ स्तर पर स्थापित होते हैं।

(स) लघु उद्योगः- मोटे तौर पर लघु उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -

(i) आधुनिक लघु विनिर्माण उद्यम व (ii) छोटे उद्यमों का मध्यवर्ती समूह ।

(i) आधुनिक लधु विनिर्माण उद्यम वह लघु विनिर्माण उद्यम हैं जो उत्पादन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः यह उद्योग बड़े शहरों या बड़े शहरों के आसपास स्थित होते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र को सहायता मिल सके। इन उत्पादों के लिये बाजार के रूप में पूरा देश उपलब्ध है और कभी कभी यह उत्पादों को बाहर के देशों में निर्यात भी करते हैं।

(ii) लघु उद्यमों का मध्यमवर्ती समूह फर्म सामान्यतः उनके उत्पादों के निर्माण के लिये पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। सामान्यतः यह समूह बिजली और मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं एवं श्रम गहन तकनीक पर आधारित होते हैं। आधुनिक लघु उद्योगों की सूची इस प्रकार हैः-

1. ऑटोमोबाइल के सामान और कल-पुर्जे।
2. धातु की ढलाई ।
3. घरेलू बिजली उपकरण जैसे प्रेस, मिक्सर आदि।
4. होजरी और उससे बने कपड़े।
5. साइकिल के कलपुर्जे और हाथ उपकरण (हैंड टूल्स)।
6. वैज्ञानिक उपकरण, भंडारण बैटरी ।
7. स्टील, कृषि उपकरण।
8. रेडीमेड (तैयार) कपड़े।

4. लघु उद्योगों की समस्याएं :

व्यवसाय संचालित करने में लघु इकाईयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्त बड़ी समस्याओं को आन्तरिक समस्या और बाह्य समस्या में वर्गीकृत किया जा सकता है। आन्तरिक समस्याओं में उद्यम की योजना, क्रियान्वयन और प्रबंधन सम्मिलित हैं। बाह्य समस्याएं व्यावसायिक माहौल से संबंधित हैं। जिनका किसी भी इकाई को सामना करना पड़ता है। लघु उद्योग इकाईयों की कुछ सामान्य समस्याओं की चर्चा इस प्रकार हैः-

(1) दोषपूर्ण नियोजन संबंधी समस्याएँ:- किसी भी योजना को प्रारंभ करने से पहले उनकी तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक विष्लेषण और बाजार सर्वेक्षण की आवष्यकता होती है। लघु उद्योगों के मामले में, अधिकांश उद्यमियों के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है और कमजोर वित्तीय अवस्था होने के कारण तकनीकी परामर्श केन्द्रों से संपर्क भी नहीं कर पाते इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

(2) दोषपूर्ण कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं:-दोषपूर्ण कार्यान्वयन से परियोजना की लागत और बढ़ जाती है।राशि जुटाने में कमी और देरी से इकाई अनाधिक हो जाती है। इससे तकनीकी जनशक्ति की अनुपलब्धता की समस्या हो सकती है।

(3) दोषपूर्ण परिचालन स्तर (चरण) समस्याएं:- परिचालन चरण के दौरान, लघु उद्योग इकाईयाँ विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करती हैं। यह समस्याएं प्रबंधन, वित्त, विपणन, जनशक्ति, तकनीक और इससे संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है। समस्याओं की व्यवस्था जमाने में उद्यमियों की योग्यता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

लघु उद्योगों की बड़ी समस्याएं इस प्रकार हैः-

(4) वित्तीय संबंधी समस्याएँ:- अधिकांश लघु उद्योग इकाईयों का पूंजी का आधार कमजोर है जिससे तकनीक विस्तार की समस्या, अभिनव उत्पादों के परिचय या नयी उत्पाद श्रृंखला के परिचय की समस्या उत्पन्न होती हैं छोटी इकाईयाँ कार्यशील पूंजी की समस्या का भी सामना करती है, जैसे जैसे कार्यशील पूंजी चक्र लंबा होता जाता है, अधिक गंभीर रूप ले लेता है। अक्सर लघु उद्योग इकाईयों को असंगठित वित्तीय बाजार से बहुत उच्च दर पर क्रेडिट का लाभ मिलता है जब वे संगठित क्षेत्र के आधार देने वाले मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

(5) दोषपूर्ण विपणन (बाजार) संबंधी समस्याएं:- लघु उद्योग इकाईयों की एक अन्य गंभीर समस्या विपणन की कमी और हस्तक्षेप है। अधिकांश लघु उद्योग इकाईयों के विपणन विभाग नहीं हैं जिसकी वजह से उनके विपणन के लिये किये जा रहे प्रयास कमजोर

पड़ जाते हैं। लघु उद्योग इकाईयाँ आधुनिक विज्ञापन, विपणन अनुसन्धान, विपणन सर्वेक्षण, उत्पाद अनुकूलन और चैनल विकास के उपायों को सहन करने की स्थिति में नहीं है।

(6) उत्पादन से संबंधित समस्याएं:- लघु उद्योग इकाईयों को बहुत सारी उत्पादन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैः- कच्चामाल की अनुपलब्धता, श्रम बल की अनुपलब्धता, तकनीकी समस्या, बिजली की कमी आदि ।

(7) श्रम संबंधी समस्याएँ:- श्रमिकों का ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी पलायन, कम वेतन और कल्याणकारी सुविधाओं में कमी, शिक्षा का निम्नस्तर और प्रशिक्षण की कमी।

(8) अन्य समस्याएं:- प्रबंधात्मक समस्याएं, संरचनात्मक समस्याएँ, बैंकों की ऋण संबंधी सुविधाओं के लिये कठोर नीतियाँ, सरकारी नियंत्रण, लघु उद्योग इकाईयों से संबंधित नीतियों में लगातार बदलाव, बड़े उद्यमों से कठिन प्रतियोगिता, भुगतान में देरी, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं आदि समस्याएं भी हैं।

5. सारांश :

लघु उद्योग वे इकाइयां हैं जो मध्यम स्तर के निवेश की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम बल की मात्रा भी कम होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का अपेक्षाकृत उत्पादन होता है। वे पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन और प्रबंधन, आदानों और आउटपुट के प्रवाह आदि के मामले में बड़े पैमाने के उद्योगों से अलग हैं। व्यवसाय में निवेश के आधार पर लघु उद्योग को परिभाषित किया जा सकता है। लघु उद्योगों के अस्तित्व की चेतना रोजगार सृजन, समानता, विकेन्द्रीकरण, गुप्त संसाधनों का उपयोग, कम पूंजी कम परिपक्वता अवधि और पिछड़े के साथ-साथ आगे के संबंध भी है। सामान्यतः लघु उद्योग इकाईयाँ बहुत सारी समस्याओं का जैसे निधि में कमी, बाजार में आने वाली बाधांए, श्रम समस्या, प्रबंधकीय समस्याएं, गुणवत्ता और उनकी नौकरशाही की समस्याएं हैं। लघु उद्योग इकाईयों को राज्य द्वारा प्रायोजित बहुत सारी प्रोत्साहन राशि मिल रही है। लघु उद्योग इकाईयों द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को संस्थागत प्रोत्साहन राशि और नीतिगत प्रोत्साहन राशि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया (2002-03), इकनोमिक सर्वे 2002-03, (नई दिल्ली: गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया) ।
2. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, प्लानिंग कमीशन (1999), नाइन्थ फाइव-ईयर प्लान (दिल्ली:प्लानिंग कमीशन)।
3. गुलाटी, मुकेश (1998), SME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ,' इन जुनेजा , जे ऐस(एड.), स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज : चैलेंजेज एंड अपॉर्च्युनिटीज़ (नई दिल्ली : एक्सेल बुक्स)।
4. नंजूदान, ऐस (1994), 'चेंजिंग रोल ऑफ़ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज : इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस , कंट्री एक्सपेरिएंसेस एंड लेसन फॉर इंडिया ,' इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली , वॉल . 29, नं. 22, (M46-M63)।
5. नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकनोमिक रिसर्च (एनसीएइआर)(1993),स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन ऑफ़ स्माल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया:लेसन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट (नई दिल्ली:NCAER) ।
6. दत्त रूद्र एवं सुन्दरम, के.पी.एम. (2006): भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चांद एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली।
7. मामेरिया, डॉ. चतुर्भज चतुर्भज एवं जैन, डॉ. एस. सी. (1995): भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा।
8. दीक्षित, ए. आर पांडे, ए.के. (2011), 'एसएमई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया: को इंटीग्रेशन एनालिसिस', द आईयूपी जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम। IX, नंबर 2, पीपी। 41-59
9. गुप्ता, आर. (2006) " 2000 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में कुटीर और लघु उद्योग का दायरा", IBS अनुसंधान केंद्र. कोलकाता
10. पूजा, (2009) "भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमों की भूमिका", भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), पीपी नंबर:12-13